

## आगजनी से रेल को 300 करोड़ का नुकसान, लेकिन खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव पूँजीपतियों को देने पर कितना नुकसान ?



हाल ही में सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ में आंदोलनकारियों द्वारा जलायी गई ट्रेनों और बोगियों से आंकड़ों के मुताबिक कुल नुकसान अधिकतम 300 करोड़ रुपए का हुआ है।

जबकि उस तुलना में अब तक लाखों करोड़ों के मूल्य की ट्रेनें, प्लेटफॉर्म, स्टेशन और रेल रुट कौड़ियों के भाव में पूँजीपतियों के हवाले कर दी जा रही हैं, उस नुकसान का ब्लोर कौन देगा ?

ये सवाल है डॉ कमल उसरी का, जो कि इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय उपायक्षम हैं।

वे कहते हैं कि जब प्रदर्शनकारियों ने रेल कोचों पर आग लगाई तब जांबाज रेल कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया।

रेल मंत्री ने भी आक्रोशित प्रदर्शनकारियों से यही कहा कि रेल जनता की ओर देश की संपत्ति है, इसलिए उसमें आग ना लगाई जाए।

और फिर एक ही सांस में वह उसी रेल को पूँजीपतियों को बेचने की नई युक्ति लगाते हैं।

देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का हक्क सिर्फ सरकार को

उनका कहना है कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का हक्क सिर्फ सरकार के पास है।

मोदी सरकार ने नवंबर 2021 में रेल के निजीकरण के लिए तरह तरह के हथकड़े इस्तेमाल किये, जिसमें से एक भारत गौरव योजना थी।

इस योजना के तहत दो साल के लिए ट्रेन का संचालन प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा।

हालांकि इन ट्रेनों का मेन्टेनेंस सरकार के ही हिस्से में होगा, प्राइवेट खिलाड़ियों को सिर्फ फीस भरनी होगी।

इस योजना में अनगिनत ट्रेनें शामिल हैं, जिसे कोई भी कानूनैकर टेन्डर डाल के ले सकेगा।

मुनाफे वाले रूट जा रहे प्राइवेट कब्जे में

यह ट्रेनें खासकर के सबसे मलाईदार रूटों पर चलाई जाएंगी, जहां भारी मुनाफा कमाए जाने का रास्ता है।

शुरुआत में जब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत पूरी ट्रेन को ही बेचने का प्रयास किया, तब बहुत काम ऑपरेटरों ने रुचि दिखाई।

जिसके बाद सरकार ने इसे लीज पर देने का फैसला किया।

रेल निजीकरण के बड़े प्लान का ही यह भारत गौरव एक छोटा सा भाग है जिसमें गौरव की आड़ में रेल की संपत्ति कौड़ियों के भाव लीज पर दी जा रही है।

कोयम्बटूर से शिर्डी तक 14 जून को चलने वाली ट्रेन भारत गौरव योजना के अंतर्गत सिर्फ पहली ही ट्रेन है।

प्राइवेट हेगी सिर्फ बुकिंग, देखरेख, सफाई सरकार के ही जिम्मे

इस योजना के तहत जिन ट्रेनों को लीज पर दिया गया है, उनकी टिकट या रिजर्वेशन की देखरेख का जिम्मा प्राइवेट मालिकों की ही होगी। लेकिन ट्रेन जिस स्टेशन में भी रुकेगी- वहां कम दामों में सफाई और मेन्टेनेंस किया जाएगा जिसका जिम्मा सरकार के पास ही है।

चूंकि यह ट्रेन दोनों धार्मिक स्थलों के बीच चलेगी, इसलिए सुरक्षा के नाम पर दो सिक्युरिटी गार्ड रखे जाएंगे।

भारत गौरव के नाम पर ट्रेन का प्राइवेट संचालन, प्रोडक्शन यूनिटों को भी निजी कब्जे में देने की तैयारी में सरकार भारत गौरव के नाम पर ट्रेनों का संचालन प्राइवेट हाथों में देने का भारी विरोध, आईआरईएफ ने कहा नहीं बेचने देंगे रेल कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन, जहां से ट्रेन रवाना हुई, वह स्वघोषित धर्मगुरु जगी वसुदेव के आश्रम के पास है। जबकि गंतव्य शिर्डी साईंगंगा था जो कि साईं बाबा के धाम के रूप में प्रचलित है।

आईआरईएफ का कहना है कि ये स्थग रूप से रेल का निजीकरण है जहां प्राइवेट ऑपरेटर अपने हिसाब से दाम तय कर रहा है।

सरकारी मान्यता प्राप्त फेडरेशन भी अड़ंगा

इस प्राइवेटाइजेशन के कदम का स्थानीय दक्षिण रेलवे एमप्लॉइंग यूनियन (DREU) ने प्रतीकात्मक विरोध किया था।

देशवासी अंदोलन के लिए IREF की रणनीति यह है कि जिन जिन स्टेशनों पर उनकी ताकत है, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाए।

वो मानते हैं कि उनकी ताकत सरकार द्वारा समर्थन और मान्यता प्राप्त फेडरेशनों जितनी नहीं है और यह भी कि ज्यादातर उनकी लडाई इर्हों फेडरेशनों से होती है।

वे कहते हैं हैं कि अगर कोई कर्मचारी सरकारी नीतियों का विरोध करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। परिवार सहित बार बार ट्रांसफर होना कर्मचारियों के लिए कठिन होता है, जिसका नीति सरकार के कर्मचारियों के मौन के रूप में मिलता है।

26 जून को संभावित है देश भर में विरोध

संभावित है कि आईआरईएफ की तरफ से 26 जून को देश भर में सरकार के निजीकरण के नीति का सिव्हालिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

इस प्लान पर अपी IREF काम कर रही है। राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत चाहे सामानों की बुकिंग हो या रेल रूट हो, सभी को लोज पर दिए जाने या प्राइवेटाइजेशन के प्लान का ही ये एक छोटा हिस्सा है।

## कोलम्बिया राष्ट्रपति चुनावः लैटिन जनता ने लिखी नई इबारत

बादल सरोज

कोलम्बिया नाम के देश की राजधानी बोगोटा हमसे 8246 मील यानी 13271 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे तय करने में बिना स्टॉपेज के लगातार हवाई यात्रा से 20 घंटे लगते हैं। भारत की प्रचलित लोक भाषा में कहें तो यह पाताल लोक है- तकीबन ठीक हमारे नीचे। इनी दूरी पर बसे देश के बारे में इन पंक्तियों को लिखते हुये और इससे कुछ अधिक दूरी पर बैठे आपके द्वारा पढ़ते हुए पहला सवाल यही कौंधा कि इत्ती दूर हुए पर क्षमता चुनाव के नीतियों पर हमें क्या खुश होना चाहिए?

कहने की जरूरत नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की वैचारिक प्रवरशि और बसुधैव कुम्भकम मानने वाले देश भारत में पैदाइश इस प्रश्न को निर्धारित करना है। फिर भी सवाल उठा है तो इसकी वजहें दृढ़ीं चाहिए।

इसकी अनेक वजहें हैं- हालांकि हमारे लिए तो इसकी एक ही वजह काफी है कि यह हमारे सर्वकालिक प्रिय लेखक गैंग्रेल गार्सिया मार्क्वेज का देश है। अपनी जादुई यथार्थवादी शैली के लिए विख्यात मार्केज (6 मार्च 1927-17 अप्रैल 2014) - कुछ लोग इन्हे मार्खेज भी उच्चारित करते हैं- स्पेनिश भाषा के उपन्यास लेखक और कथाकार थे। 70-80 के दशक से उनकी अंग्रेजी और हिंदी में अनूदित लगभग हर किताब बूँदकर और उस जमाने में खरीद कर पढ़ी है जब पॉकेट मनी के नाम पर मात्र अठनी मिला करती थी। उनकी नोबल सम्मानित हुड्डे इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड (एकांत के सौ बरस) कृति एक असाधारण उपन्यास है। इसे पढ़ा जाना चाहिए।

यूं तो उनका लिखा हर शब्द पठनीय है मगर फिर भी जिहें बिना इतिहास पढ़े, लैटिन अमेरिकी साम्राज्यवाद का आखिरी विकट था। क्यूंकि में पिछले 6 दशक से भी ज्यादा समय से क्युनिस्ट हुकूमत है। ह्यूगो शावेज के बाद से अब बस ड्राइवर निकोलस मादुरो तक बेनेजुएला में वामपंथ अडिङ है। बोलीविया में इवो मोरालेस से शुरू हुआ वामपंथी दौर लुइस आर्क के राष्ट्रपति बनने तक जारी है। पिछली साल ही चिली, पेरू और होंडुरास नाम के देशों में वामपंथी राष्ट्रपति जीते हैं। ब्राजील भी कुछ महीनों में जुझारू वाम नेता लूला डी सिल्वा को फिर से चुनने जा रहा है। गरज ये कि संयुक्त राज्य अमरीका- यूएसए- का पिछवाड़ा कहे जाने वाले महाद्वीप ने साम्राज्यवाद के पिछवाड़े पर लात मारकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

कि कोलम्बिया सामान्य देश नहीं है। यह मुट्ठी भर धनपिशाचों -ओलिगार्क- की जड़न में जकड़ा यातनागृह है। यह दुनिया की नशे की राजधानी-ड्रा कैपिटल- है, जहां बर्बर ड्रा तस्करों की तूती बोलती है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहा जाने वाला पाल्बो एस्कोबार, कोकीन का अब तक का सबसे चालबाज सौदागर यहीं का था। आज भी सबसे ज्यादा कोकीन का निर्यात यहीं से होता है। इस ड्रा माफिया का सरकार के हर तंत्र पर कब्जा है। इनके विरोध में जो भी बोलता है उनकी हत्या करवा देना आम बात है। पिछले समय में राष्ट्रपति पद के जिन जिन उम्मीदवारों ने इस ओलिगार्की के खिलाफ आवाज उठाई वे दिनदहाड़े मार डाले गए। इनमें जॉन एलीसर गैटन, जैमे पार्टी लील, बरनार्डो जरामीलो, कार्लोस पिजारो, लुइस कार्लोस गलन शामिल हैं।

कि यहां जब जब वामपंथ ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को संगठित करने की कोशिश की, उनका कल्पना जैसा कर दिया गया। पेट्रोटिक यूनियन इसकी मिसाल है। पिछले 8 वर्षों में इस पार्टी के 1163 नेता मार डाले गए। इनमें हड्डी वर्षों में राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार, 13 सांसद और 11 महापौर शामिल हैं। इस लिहाज से यह जी